तथा उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के गलत साबित होने की जांच तथा मूल्यांकन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी हां, सरकार ने समपादकीय देखा है।

(ख) से (घ) मानसून मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए वर्तमान मॉडल 1988 में क्रियाशील किया गया था और तब से मानसून पूर्वानुमान संतोषजनक सिद्ध हुआ है। 1994 में मॉडल ने एक सामान्य मानसून का सही अंदाजा लगाया था, लेकिन वास्तविक की अपेक्षा कम कुल वर्षा की भविष्यवाणी की थी। पूर्वानुमान तकनीकों में सुधार की सतत समीक्षा की जाती है।

Non-Conventinal Power Production

466. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering to promote Small Power Plants under reliable renewable energy and technologies utilising bio-mass, bio-gas solar thermal etc., at the village level;

(b) whether Government are considering setting up of a separate Corporation for promoting Non-Conventional Power production at the village level; and

(c) if not, whether Government are considering to promote genreating of non-conventional energy in the Rural Sector in association with Rural Electrification Corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Government promoting use of solar photovoltaics, small hydro and biomas gasifier technologies for village electrifications in a decentralised manner. These technologies are proven and also cost economic under site conditions.

(b) No, Sir.

(c) Rural Electrification Corporation is already involved in electrification of remote village with locally available renewable energy resources.

"कापार्ट" द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को काली सूची में डाला जाना

467. **श्री रामदेव भंडारी**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कापार्ट) द्वारा राज्य-वार कितने स्वयंसेवी संस्थाओं को काली सूची में डाला गया है;

(ख) इन संस्थाओं को काली सूची में डालने का आधार तथा कारण क्या है तथा इस संबंध में जांच करने वाली एजेंसी का नाम क्या है;

(ग) काली सूची में दर्ज इन संस्थाओं को "कापार्ट" द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है और उसमें से कितनी धनराशि के दुरुपयोग होने का अनुमान है;

(घ) धनराशि के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उन संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में धनराशि के दुरुपयोग की "कापार्ट" द्वारा जांच की जा रही है; और

(च) क्या "कापार्ट" काली सूची में दर्ज संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) कापार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठनों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) इन स्वयंसेवी संगठनों को कापार्ट द्वार मुख्य से निधियों के दुरुपयोग। झूठी सूचनाएं, फर्जी दस्तावेजों आदि के आधार पर काली सूची में डाला गया है। मुख्य एजेंसियों में ऐसे मामलों की जांच करने वाले मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में कापार्ट द्वारा प्रतिनियुक्त परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा की जाती है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

(च) जी हां।

विवरण

राज्य	31.7.1995 तक कापार्ट द्वारा कानी सूची में डाली गई स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या (अंतिम)
1. असम	4
2. आन्ध्र प्रदेश	72
3. बिहार	71
4. दिल्ली	19
5. गुजरात	13
6. हरियाणा	6
7. हिमाचल प्रदेश	1
8. केरल	4
9. कर्नाटक	16
10. मध्य प्रदेश	14
11. महाराष्ट्र	14
12. मणिपुर	2
13. उड़ीसा	7
14. राजस्थान	27
15. तमिलनाडु	7
16. उत्तर प्रदेश	74
17. पं॰ बंगाल	8
कुल	359

National Programme for Control of Blindness

468. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the activities undertaken with the assistance of World Health Organisation (WHO) under the National Programme for Control of Blindness;

(b) the States where the assisted project has been taken up; and

(c) whether any monitoring cell has been formed for the avaluation purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) World Health Organisation (WHO) funds are used for supply of opthalmic equipments, training of manpower and strengthening of Management Information System (MIS) at the Central level.

(b) These activities are not specified to any particular State.

(c) Yes, Sir.

Life-saving Devices

469. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Defence technology being used to make life-saving devices" as reported in the Economic Times dated 3rd July, 1995;

(b) whether scientists in the country are using military technology to make life-saving devices, like cardiac pace-makers;

(c) if so, whether Government would use the cardiac pace-makers being developed by scientists; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Defence Research & Development Organisation have successfully developed an external pacemaker for intensive care application. This development work has been sponsored by Society for Bio-Medical Technology (SBMT). The external pacemaker is under clinical trials at Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. The implantable version of the pacemaker is under advanced stages of development. After acceptance in clinical trials and productionisation, the cardiac pacemaker would be available for use to general public and hospitals, both in Government and private sectors. The SBMT has already nominated an industry unit in private sector as production agency.